would like to know from the hon. Minster: how much money has been allotted to the State Government of Kerala for this project? At the same time, we do not require linking of rivers in Kerala, as water is always flowing around the coastal areas.

श्री दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी : सभापति महोदय, यह पश्चिम तट केरल की ओर आता हैं उसके लिए 65 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया हैं।

श्री सभापति : मंत्री जी ने पहली बार जवाब दिए हैं। उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। इसके लिए इनको इनकरेज करना चाहिए।

Financial assistance to NGOs and various organisations

83. SHRIDWIJENDRA NATH SHARMAH: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) the details of financial assistance granted to various voluntary organizations and NGOs functoning at present in different parts of the country during the last three years, NGO-wise/State-wise;

(b) whether some proposals received from the State of Assam for providing grants to NGOs are pending with Government;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps being taken by Government to clear all the pending proposals for providing financial assistance to NGOs in the State of Assam?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (DR. SATYA NARAYAN JATIYA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Ministry of Social Justice and Empowerment has released grant-in-aid assistance to NGOs in the last three years and current financial year as under:

(Rs. in crores)

SI. No.	Items	Year			
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003 (as on 20.02.03)
1	No. of NGOs	2056	1961	2665	2375
2	Amount released	153.48	161.65	190.20	185.63

State-wise details are annexed as Statement-! (See below)

(b) to (d) In respect of Assam, 165 cases have been sanctioned in the last three years and during the current financial year (upto 20th February 2003). Presently, 75 cases are awaiting final decision for want of requisite documents, specified in the scheme applied for, inspection reports from the State Governments/clarifications from the NGOs.The NGOs and the State Governments are being pursued to furnish the requisite information so that appropriate decisions on the applications can be taken

Statement-I

Statewise No. of NGOs & Amount released during the last three years

SI. No.	Name of the State/UT	1999-2000 No. of NGOs	1999-2000 Amount released	2000-01 No. of NGOs	2000-01 Amount released	2001-02 No. of NGOs	2001-02 Amount released
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Andhra Pradesh	323	2413.36	317	2286.05	397	2639.52
2	Arunachal Pradesh	2	13	1	6.32	4	45.18
3	Assam	37	142.36	45	211.4	57	203.8
4	Bihar	46	238.04	32	345.72	75	534.94
5	Chhattisgarh	0	0	1	9.08	9	37.11
6	Goa	6	33.17	6	24.87	9	44.5
7	Gujarat	60	347.62	74	716.11	87	493.21
8	Haryana	59	248.67	56	363.97	63	259.6
9	Himachal Pradesh	4	69.29	13	126.01	12	63.04
10	Jammu & Kashmir	9	28.91	15	108.78	16	134.8
11	Jharkhand	0	0	2	7.35	10	24.24
12	Karnataka	133	1014.6	128	1116.2	183	1270.99
13	Kerala	82	635.86	92	703.61	107	784.42
14	Madhya Pradesh	60	300.05	66	297.17	111	446.06
15	Maharashtra	151	872.05	135	903.15	222	1069.19
16	Manipur	108	369.8	91	411.8	111	347.54
17	Meghalaya	6	27.38	6	59.79	9	71.44
18	Mizoram	9	78.11	11	84.21	9	91.96
19	Nagaland	8	49.86	8	46.07	13	50.63
20	Orissa	149	1195.7	136	1059.7	184	1284.72
21	Punjab	49	256.56	42	317.41	48	299.9

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Rajasthan	40	611.77	46	643.9	113	801.49
23	Sikkim	1	3.12	2	5.47	4	7.18
24	Tamil Nadu	132	762.7	112	742.32	163	909.59
25	Tripura	11	26.65	9	36.24	11	53.55
26	Uttar Pradesh	349	2964.95	243	2792.96	301	3653.77
27	Uttaranchal	0	0	9	117.05	28	194.64
28	West Bengal	155	1163.28	150	1337.4	171	1547.2
29	Andaman & Nicobar Island	1	0,55	1	1.58	1	5.28
30	Chandigarh	5	32.03	6	33.29	6	16.6
31	Dadra & Nagar Haveli	0	0	0	0	1	1.53
32	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0
33	Delhi	53	1431.75	102	1227.29	125	1607.98
34	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0
35	Pondicherry	8	16.99	4	22.65	5	22.48
	TOTAL:	2056	15348.18	1961	16164.92	266	19019.56

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: Sir, the reply of the Minister shows that huge amount of money has been granted to the NGOs in the country. I would like to know from the hon. Minister whether there is any specific policy for giving financial assistance to the NGOs who are working for the weaker sections of the society, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, backward classes and minorities. I would also like to know whether there is a separate policy for the benefit of these sections of the society. If so, has the Government publicised that policy so that the weaker sections of the society could know about this policy of the Government?

डा. सत्य नारायण जटिया: माननीय सभापति जी, हमने मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाली सभी योजनाओं के संदर्भ में काम्प्रिहेंसिव तरीके से एक हैंडबुक, मार्गदर्शक पुस्तिका निकाली हुई हैं । उसमें प्रत्येक योजना के बारे में यह उल्लेख किया गया हैं कि किस तरह से योजना को एप्लाई करना चाहिए, उसकी प्रक्रिया क्या हैं? वह पुस्तक खरीदी भी जा सकती हैं और ऐसे भी जब किसी को उसकी आवश्यकता होती हैं तो हम उसे वह पुस्तक देने का काम भी करते हैं । जहां तक मेरे मंत्रालय का संबंध हैं , उसमें इन सारे वर्गो के लिए ,जो अनुसूचित जाति के हैं, जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं , सभी प्रकार के अल्पसंख्यक हैं, वृद्ध तथा विकलांग बच्चों के लिए भी

हमारी योजनाएं काम कर रही हैं और स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से हम इन सारे कामों को चलाते हैं ।

श्री सभापति: मंत्री जी, एक पुस्तक आप इनके पास भिजवा दीजिए ।

डा. सत्य नारायण जटिया: जी, मैं इन्हें जरुर भेंट कर दूंगा।

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: My second supplementary is this. What is the actual allocation of funds to the State of Assam during this year? How much money has been given to the NGOs to work in the State of Assam?

डा.सत्य नारायण जटिया : एन.जी.ओज़ के लिए जो खर्चा हम कर रहे हैं, वह विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अलग-अलग हैं । असम में जो एन.जी.ओज़ काम कर रहे हैं , 1999-2000 में ऐसे 37एन.जी.ओज़ थे और उनको जो राशि निर्मुक्त की गई थी , वह 1,42,36,000 थी । 2000-01 में 45 एन.जी.ओज़ काम करते थे और उनको निर्मुक्त की गई राशि 2,11,04,000 थी । 2001-02 में 57 एन.जी. ओज़ काम करते थे और उनको निर्मुक्त की गई राशि 2,03,28,000 थी । इस बारे में यदि माननीय सदस्य और कुछ विशेष जानकारी चाहेंगे तो हम जरुर उपलब्ध कराएंगे।

DR. M.N. DAS: It is good of the Government that it sanctions huge amount of money to different NGOs spreading all over the country. Is there any mechanism to supervise the working of the NGOs? Are there some fake NGOs working? Is the money spent properly? Or is it shown only on papers that NGOs are working and money is being spent?

डा. सत्य नारायण जटिया: एन.जी.ओज़ के कार्यकरण पर समय-समय पर उनकी कार्य- पद्वति को देखने का काम भी हमारा मंत्रालय करता हैं । जिन एन.जी.ओज़ को, स्वैच्छिक संग़ठनों को हम राशि मंजूर करते हैं, उसके तुरंत बाद ही दूसरी किश्त निर्गत करने से पहले उसका निरीक्षण करने का काम भी हम करते हैं । मंत्रालय के अंतर्गत यह सारा काम होता हैं और जो एन.जी.ओज़ ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं, उनको हम ब्लैकलिस्ट भी करते हैं । विगत समय में हमनेऐसे ठीक प्रकार से काम नहीं करने वाले जिन एन.जी.ओज को ब्लैकलिस्ट किया हैं , उनकी संख्या 66 रही हैं ।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, so much of money is released to the NGOs, and as an hon. Member has earlier submitted, where is the mechanism of the Government of India to have a thorough enquiry about the activities and expenditure of these NGOs? What is the

role of the State Governments? Sir, the NGOs are neither responsible to the local Governments nor to the State Governments. I would like to know how many NGOs were blacklisted during the last year.

डा. सत्य नारायण जटिया: सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा कि एन.जी.ओज काम करती हैं उनके विरुद्व कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं। जिनके खिलाफ शिकायत आती हैं उनकी जांच करने का काम हम करते हैं और राज्य सरकारों के माध्यम से भी हम उसके बारे में रेकमेंडेशन मंगाने का काम करते हैं कि कौन सी एन.जी. ओज ठीक प्रकार की हैं और कौन सी नहीं हैं। राज्य सरकार की सिफारिश आने के बाद हम मंत्रालय में सारी प्रक्रिया करते हैं जिसके अंतर्गत एन.जी.ओज़ सहायता निर्मुक्त की जाती हैं और उसकी जांच करने के आधार पर यदि कोई बात ठीक नहीं हैं तो हम राज्य सरकार को पुन:लिखते हैं कि आप इस बारे में जांच करें। जैसा कि मैंने पहले बताया हैं कि इस प्रकार की 66 एन.जी.ओज़ जो कि ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही थीं उनको हमने ब्लैक लिस्ट किया हैं। यह कार्यवाही हम निरंतर करते जाते हैं जिसमें कि गैर-सरकारी संगठनों का काम रहता हैं। उनका निरीक्षण करने की पद्वति भी हमने बनाई हुई हैं। इस काम के लिए मंत्रालय में भी हमने पूर्व सेक्रेटरी के अंतर्गत एक समिति बनाई हैं जो कि इस सारी पद्धति को ठीक प्रकार से प्रमाणित होने की दृष्टि से जांच करने के लिए भी और नेशनल उपाय सुझा रही हैं।

श्री सभापति: आप एक बात बताइये, यह सब राज्य सरकारों और आपको तो पता हैं, लेकिन क्या जनता को इस प्रकार की जानकारी हैं या नहीं कि एनजी ओज़ को किस प्रकार से काम करना चाहिए, उन्हें कितनी धनराशि उपलब्ध हुई हैं और कितना उसका उपयोग हुआ हैं? क्या इस बारे में कोई व्यवस्था हैं जिससे कि जनता को यह जानकारी मिल सके?

डा. सत्य नारायण जटिया: सभापति जी, यह एक ऐसा क्षेत्र हैं जिसमें कि एनजीओज के माध्यम से हैं, चूंकि सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह उन सारी बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करे। हालांकि सब एनजीओज एकदम कोई बहुत ही ठीक प्रकार से काम भी नहीं कर रही हैं।

श्री सभापति: आप इस पर विचार करिए ताकि जनत को इसकी जानकारी दी जाए।

डा. सत्य नारायण जटिया**:** ठीक हैं।

प्रो. राम देव भडारी : महोदय, समाचार-पत्रों के माध्यम से आप जनता तक पहुंचाइये।